अनुबोधन, खण्ड 1, अंक 3, सितम्बर 2025, पृष्ठ 63–68
ISSN: 3049-4184 (प्रिन्ट), 3108-1185 (ऑनलाइन)
प्रकाशित: 30 सितम्बर 2025
जर्नल वेबसाइट: https://anubodhan.org

डोनाल्ड ट्रंप 2.0 और भारतः तनाव के साथ सौदेबाजी का दौर

डॉ. शक्ति जायसवाल*

हांस जे0 मॉर्गेंथाऊ ने अपनी पुस्तक Politics Among Nations (1948)[1] में ही बताया था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल सार शक्ति की राजनीति है। राज्य अपने राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन के आधार पर एक–दूसरे से सौदेबाजी करते हैं। नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थाएँ केवल सीमित महत्व रखती हैं। थॉमस शेलिंग[2] के अनुसार बर्गेनिंग सिर्फ शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि धमकी (Threats), वचनबद्धता (Commitments), और विश्वसनीयता (Credibility) के ज़रिए चलती है। आज 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल 2.0 में उपरोक्त राजनीतिक वैज्ञानिकों के विचार व्यावहारिक धरातल पर नजर आ रहे हैं।

जब डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो पूरी दुनिया ने उनकी विदेश नीति में "अमेरिका फर्स्ट" (America First) दृष्टिकोण को महसूस किया। भारत के लिए भी यह कार्यकाल कई मायनों में अहम साबित हुआ। 2020 तक भारत–अमेरिका रिश्तों में रक्षा, रणनीति और व्यापार को लेकर नई ऊर्जा आई। लेकिन ट्रंप का नेतृत्व पारंपरिक अमेरिकी कूटनीति से हटकर रहा है। उनका निर्णय लेने का तरीका व्यक्तिगत संबंधों और व्यापारिक सोच पर आधारित रहा है। ऐसे में भारत के लिए ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 2.0 नए चुनौतियों जन्म दे रहा है। ट्रंप की विदेश नीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित रहीः–

1. **अमेरिका फर्स्ट नीति**– हर अंतरराष्ट्रीय समझौते में अमेरिका के हित सर्वोपरि।
2. **व्यापार पर ध्यान**– द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम करना और

*एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बुद्ध विद्यापीठ पी0जी0 कॉलेज, नौगढ़–सिद्धार्थनगर, E-mail: shaktijaiswal59@gmail.com

अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देना।

3. **राष्ट्रवाद और सुरक्षा**– चीन और इस्लामिक आतंकवाद पर कड़ा रुख।

भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल मिश्रित स्थिति का रहा है। एक ओर ट्रंप 1.0 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीबी संबंधों में दिखे ("Howdy Modi" और "Namaste Trump" जैसे कार्यक्रम इसका उदाहरण हैं), वहीं दूसरी ओर ट्रंप 2.0 द्वारा व्यापार और वीज़ा नियमों में सख्ती भी देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रम्प 2.0 के प्रचार अभियान में दो प्रमुख मुद्दो को जोर–शोर से उठाया गया था। एक अवैध प्रवासी दूसरा टैरिफ। ट्रंप 2.0 में बार–बार कह रहे थे कि अमेरिका को विश्व नेतृत्व के बजाए घरेलू अर्थ व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, इसलिए वह मानवाधिकार परिषद, पर्यावरण संधि, डब्ल्यू.एच.ओ. एवं विदेशी फंडिंग से पीछे हट रहे थे। 100 अवैध प्रवासियो को 05 फरवरी–2025 अमेरिकी सेना के एक विमान द्वारा अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया।[3] इसके अतिरिक्त ट्रंप 2.0 भारत पर टैरिफ बढ़ाने एवं अपने देश में रोजगार एवं मैन्यूफैक्चरिंग के अवसर बढ़ाने पर भी जोर देते नजर आये।

भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 2.0 की तल्ख़ी के कई दूसरे कारण हैं।[4]

1– ब्रिक्स को लेकर अमेरिका की नाराजगी

ब्रिक्स, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वे समय–समय पर ब्रिक्स देशों को 100 प्रतिशत तक टैरिफ़ लगाने की धमकी देते आए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतरराष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ था। डॉलर की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का दबदबा है। फ़ोर स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल बिज़नेस और भू–राजनीति के प्रोफ़ेसर फ़ैसल अहमद का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। वो कहते हैं, "इसमें अब ईरान भी आ गया है, लोकल करेंसी की बात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है। डॉलर को तभी कमज़ोर किया जा सकता है जब आप मजबूत

होंगे। अगर टैरिफ़ ज्यादा लगेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। वहीं, दूसरी तरफ थिंक टैंक गेटवे हाउस की फेलो नयनिमा बासु कहती हैं, "ब्रिक्स के अन्य देश काफी चीजें लाना चाहते हैं लेकिन वे भारत के सुस्त रवैये के चलते नहीं ला पाते। भारत पर ये आरोप बार–बार लगता है कि वह अमेरिका के कारण ब्रिक्स को कमज़ोर कर रहा है। वे कहती हैं, "ब्रिक्स के अन्य देश भी अमेरिका पर निर्भर हैं, सिर्फ़ भारत ही अकेला नहीं है। बावजूद इसके भारत को इस तरह के अमेरिकी टैरिफ़ का सामना करना पड़ रहा है।

2– ट्रेड डील पर सहमति का न बन पाना

अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रंप का मानना है कि भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका के लिए भारतीय बाज़ारों को खोलने का काम करेगी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। नयनिमा बासु कहती हैं, "भारत ट्रेड डील के वादे से पीछे हटा है, हालांकि उसके अपने वाजिब कारण हैं, क्योंकि अमेरिका भारतीय बाज़ार में ज्यादा एक्सेस मांग रहा है। एक्सपर्ट नयनिमा बासु भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार आठ अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका से मेवे, सेब और दाले मंगवाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ने अमेरिका को रियायतें दीं तो वह किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएगा और यह भारत में एक बड़ा मुद्दा है। वहीं डेयरी उत्पाद और चावल, गेंहू वो चीजें हैं, जिन पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

3– चीन के साथ नजदीकी

2020 में गलवान घाटी में भारत–चीन सैन्य झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चीन यात्रा करने जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। पिछले साल अक्तूबर में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कज़ान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाक़ात की थी। जून, 2025 में राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजिंग भी पहुंचे थे। उसके बाद विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी चीन गए। जामिया

मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रेशमी काज़ी का कहना है कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। रेशमी काज़ी कहती हैं, "अमेरिका को अगर कोई देश चैलेंज कर रहा है तो वह चीन है। एक समय इस भूमिका में रूस था, लेकिन अब चीन उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। नयनिमा बासु कहती हैं, "भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के चीन जाने के बाद बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। चीन इसकी मांग कर रहा है। वीजा पाबंदियां भी आने वाले समय में हट जाएंगी। वे कहती हैं, "यह सब अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है, रूस से तेल खरीदने को वह सिर्फ़ बहाना बना रहा है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद भी कर देता है तो क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ़ नहीं लगाएगा?" बासु का कहना है, "पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ़ किंग' बताया था। इसलिए टैरिफ़ से बचना तो मुश्किल ही था। इतना ज़रूर हो सकता था कि वो एक सीमा में रहे हैं। वे कहते हैं, "अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ़ नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर करता आया है। ट्रंप की भारत के साथ नाराज़गी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ़ हर देश लगाता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट चाहता है। प्रो0 फ़ैसल कहते हैं, "भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना नहीं की जा सकती। भारत का ज़ोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर रहा है।

4– ऑपरेशन सिंदूर रोकने का श्रेय न मिलना

पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति जितना नरम दिखते थे, इस बार उतना ही कड़क नज़र आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि बाद में दोनों देशों ने संघर्ष विराम का एलान किया था। राष्ट्रपति ट्रंप बार–बार यह दावा करते रहे हैं कि सीजफायर उन्होंने कराया है, जबकि भारत ने साफ़ किया है कि इसमें अमेरिका की भूमिका नहीं है। जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में बदल गया था। नयनिमा बासु का कहना है, "ट्रंप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी उन्हें कोई श्रेय दें या कम से कम एक फोन कॉल करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं

हुआ, जो एक नाराजगी का कारण दिखाई देता है। प्रो0 रेशमी काज़ी का भी ऐसा ही मानना है। वे कहती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतना चाहते हैं। उनका कहना है, "पाकिस्तान, कंबोडिया और इसराइल जैसे देश राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल देने मांग कर चुके हैं, वहीं भारत इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है।

5– नॉन टैरिफ़ बैरियर

टैरिफ और नॉन टैरिफ़ के बीच का फर्क व्यापार नीति और आयात–निर्यात के नियंत्रण से जुड़ा है। प्रोफ़ेसर फ़ैसल अहमद का कहना है, "जब किसी सामान के आयात–निर्यात पर कर लगता है तो वह टैरिफ़ कहलाता है, वहीं नॉन टैरिफ़ में किसी सामान की मात्रा को सीमित करना, लाइसेंसिंग, जांच और गुणवत्ता नियम जैसी चीजें शामिल होती हैं। वे कहते हैं, "अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ़ नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर करता आया है। ट्रंप की भारत के साथ नाराज़गी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ़ हर देश लगाता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट चाहता है।"

प्रो0 फैसल कहते हैं, "भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित। इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना नहीं की जा सकती। भारत का ज़ोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर रहा है"।

इस प्रकार सितंबर 2025 तक ट्रंप 2.0 में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि दुनिया का नेतृत्व करने की बजाय वह ट्रांजैक्शनल (लेन–देन वाला) द्विपक्षीय रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह दबाव का इस्तेमाल करेंगे। अपनी आर्थिक और तकनीक की ताक़त का इस्तेमाल करेंगे। रॉबर्ट डाहल अपनी पुस्तक Who Governs? (1961)[5] में कहा कि राजनीति मूलतः सौदेबाजी (Bargaining) और समझौते (Compromise) की प्रक्रिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्य और गैर–राज्य अभिनेता (NGOs, MNCs,) अंतरराष्ट्रीय संगठन) एक–दूसरे से नेगोशिएशन और लॉबिंग करते हैं। उनके दृष्टिकोण में शक्ति का विकेंद्रीकरण (Diffusion of Power) होता है, यानी केवल सैन्य शक्ति ही निर्णायक नहीं है।

इस तरह ट्रंप 2.0 प्रशासन का भूराजनीतिक नजरिया बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के अवमूल्यन पर केंद्रित लगता है,[6] चाहे वह डब्ल्यू.एच. ओ., डब्ल्यू.टी.ओ. और संयुक्त राष्ट्र को मदद की अमेरिकी प्रतिबद्धताओं

से पीछे हटना हो, या नाटो सहयोगियों को नोटिस पर रखना। इन संकेतों के मद्देनजर, नयी दिल्ली को एक ऐसे अमेरिकी प्रशासन के लिए तैयार रहना होगा जो भारत की चिंताओं को लेकर विशेष संवेदनशील नहीं होगा या जब तक उसे अपने लिए फायदा नहीं दिख रहा हो वह भारत के विकास में तत्पर सहयोगी नहीं होगा। इसके बजाय, उसे ट्रम्प युग की किसी प्रतिकूल कार्रवाई से होने वाले नुकसान को सीमित करने की ओर बढ़ते हुए, एक ज्यादा लेन–देन आधारित राह बनानी होगी।

सन्दर्भ :

1. मॉर्गेंथाऊ, हांस जे0, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, 1948
2. शेलिंग, थॉमसः The Strategy of Conflict, 1960
3. राय, संदीपः अवैध भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप से सीधे न टकराने की क्या है, मोदी सरकार की रणनीति, बी0बी0सी0 न्यूज हिन्दी, 06 फरवरी–2025
4. गोयल, अभिनव, डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज है? ये हैं पांच बड़ी वजहें, बी.बी.सी. न्यूज हिन्दी, 07 अगस्त–2025
5. डाहल, रॉबर्टः ''Who Governs? (1961)''
6. The Hindu: Change Dynamics, on India & the Trump Administration, 23 January 2025

Copyright © 2025 Siri Research Foundation. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0).